Q.1) भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।
2. सभी राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थानों का निर्माण कर, त्रि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया।
3. 1960 के दशक में ये पंचायती राज संस्थान अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1 और 3

Q.1) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।	यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थानों का निर्माण किया, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में, संख्या के संबंध में, समति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संरचना, कार्य, वित्त और अन्य पर विभिन्नता थी। उदाहरण के लिए, राजस्थान ने त्रि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया जबकि तमिलनाडु ने द्वि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया।	1960 के दशक की ये पंचायती राज संस्थाएं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित थीं। अशोक मेहता समिति की नियुक्ति 1977 में हुई थी।

Q.2) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग- IX जोड़ा है।
2. अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायोचित भाग (justiciable part) के अंतर्गत में लाया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत के संविधान में एक नया भाग- IX जोड़ा है। यह भाग	अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा देता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग

'पंचायतों' के रूप में उल्लेखित है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान शामिल हैं।	(justiciable part) के अंतर्गत में लाया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं।

Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा का सही विवरण है, जैसा कि 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है?

a) यह एक ऐसा निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क शामिल होते हैं।
b) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
c) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं।
d) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं।

Q.3) Solution (b)

ग्राम सभा एक निकाय है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल एक गाँव की मतदाता सूची में गाँव स्तर पर पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार, यह एक ग्राम सभा है जिसमें एक पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।

Q.4) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सभी स्तरों पर पंचायतों के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
2. सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।	मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से तथा उसके अपने चुने गए सदस्यों में से किया जाएगा। हालाँकि, ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत के अध्यक्ष को इस तरह से चुना जाएगा जैसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है।

Q.5) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सीटों के आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई के आरक्षण का प्रावधान है।
2. यह अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
अधिनियम में पंचायत क्षेत्र में कुल आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत (यानी सभी तीन स्तरों पर) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, राज्य विधायिका गांव में पंचायत में अध्यक्ष के कार्यालयों या किसी अन्य स्तर पर एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रदान करेगी।	अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होने का प्रावधान है (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित)। इसके अलावा, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या की न्यूनतम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

Q.6) भारत में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. विघटन के मामले में, किसी भी परिस्थिति में, अपने विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पंचायत का गठन करने के लिए नए चुनाव होने चाहिए।
2. समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित की गई पंचायत का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष के लिए नहीं होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
अधिनियम प्रत्येक स्तर पर पंचायत को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रावधान प्रदान करता है। हालांकि, यह अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग हो सकती है। इसके अलावा, पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले (a) पूरे किए जाएंगे; या (b) विघटन के मामले में, इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले।	विघटन के बाद, गठित एक पंचायत की अवधि, पहले की शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए भंग की गई पंचायत जारी रहती, यदि यह भंग नहीं होती। दूसरे शब्दों में, समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित की गई पंचायत पांच वर्ष की पूरी अवधि का आनंद नहीं लेती है, बल्कि शेष अवधि के लिए कार्यालय में ही रहती है।

लेकिन, जहां **शेष अवधि** (जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रही होगी) **छह महीने से कम है**, तो ऐसी अवधि के लिए **नई पंचायत के गठन के लिए कोई चुनाव आयोजित करना आवश्यक नहीं** होगा।	

Q.7) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक संवैधानिक प्रावधान होने के नाते, अधिनियम भारत के सभी राज्यों में लागू है।
2. संसद यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे, जैसा कि यह निर्दिष्ट कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**असत्य**
यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में (a) अनुसूचित क्षेत्रों और राज्यों में आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं; (b) मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है; और (c) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। हालाँकि, संसद इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन विस्तारित कर सकती है, जैसे इसे निर्दिष्ट कर सकती हैं।	भारत का राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है।

Q.8) निम्नलिखित में से किसे 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधानों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है?

1. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
2. तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।
3. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।
4. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2

c) 2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य

अनिवार्य प्रावधान
1. एक ग्राम या ग्रामों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वोटिंग अधिकार।
6. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।
8. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें (दोनों सदस्य और चेयरपर्सन) का आरक्षण।
9. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना तथा किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए चुनाव कराना।
10. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
11. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।

स्वैच्छिक प्रावधान
1. ग्राम स्तर पर शक्तियों और कार्यों को ग्राम सभा को हस्तांतरण।
2. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण करना।
3. मध्यवर्ती पंचायतों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना या राज्य में मध्यवर्ती पंचायतों न होने की स्थिति में, जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
4. जिला पंचायतों में मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना।
5. अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर आने वाले विभिन्न स्तरों पर संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
6. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।
7. पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, ताकि वे स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें (संक्षेप में, उन्हें स्वायत्त निकाय बनाकर)।
8. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को पूरा करने के लिए पंचायतों पर शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण;।
9. पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क और फीस, टोल, आदि के लिए अधिकृत करना।
10. एक पंचायत को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोलों और फीस को सौंपना।
11. राज्य के समेकित कोष से पंचायतों को अनुदान देना।
12. पंचायतों के सभी धन संग्रहित करने के लिए धन के गठन का प्रावधान।

Q.9) जिला योजना समिति (District Planning Committee) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करती है।
2. राज्यपाल के पास ऐसी समितियों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है।

3. 74 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, इसके चार- पांचवें (4/5) सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए, तथा समग्र रूप से जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन करेगा।	राज्य विधायिका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकती है: 1. ऐसी समितियों की संरचना; 2. ऐसी समितियों के सदस्यों के चुनाव का तरीका; 3. जिला योजना के संबंध में ऐसी समितियों के कार्य; तथा 4. ऐसी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव का ढंग।	यह अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि जिला योजना समिति के सदस्यों में से चार- पांचवें (4/5) सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने जाने चाहिए। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।

Q.10) नगर निगमों (Municipal Corporations) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये भारत के राष्ट्रपति के आदेश से केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित होते हैं।
2. नगर निगम आयुक्त, निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर और अन्य जैसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए नगर निगम बनाए जाते हैं। वे राज्यों में संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों और भारत के संसद के अधिनियमों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक सामान्य अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम हो	नगरपालिका आयुक्त परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार, वह निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और आम तौर पर आईएएस का सदस्य होता है।

सकता है।	

Q.11) अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे शहर के प्रशासन के लिए बनाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
चूंकि यह सरकारी गजट में एक अधिसूचना द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के भीतर कार्य करता है, लेकिन अधिनियम के केवल वही प्रावधान इस पर लागू होते हैं जो सरकारी गजट में अधिसूचित किए जाते हैं जिसके द्वारा इसे बनाया जाता है। इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत कार्यान्वयन शक्तियों को भी सौंपा जा सकता है। **यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।**	दो प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र समिति बनाई गई है - औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहा शहर, तथा एक नगर जो अभी तक नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन जिसे अन्यथा राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है।

Q.12) भारत में शहरी स्थानीय शासन (urban local governance) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
2. सड़कें और पुल, बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगरपालिकाओं के अंतर्गत आते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**

राज्यों ने नामित गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कुछ एजेंसियों की स्थापना की है जो 'वैध रूप से' नगर निगमों या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शहरी सरकारों के डोमेन से संबंधित हैं। कुछ ऐसे निकाय हैं: 1. नगर सुधार न्यास। 2. शहरी विकास प्राधिकरण। 3. जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। 4. हाउसिंग बोर्ड। 5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 6. बिजली आपूर्ति बोर्ड। 7. शहरी परिवहन बोर्ड। ये कार्यात्मक स्थानीय निकाय राज्य विधायिका के एक अधिनियम या एक कार्यकारी संकल्प द्वारा विभागों के रूप में वैधानिक निकायों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। वे स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करते हैं तथा स्थानीय शहरी सरकारों, अर्थात् नगर निगमों या नगर पालिकाओं और अन्य में स्वतंत्र रूप से आवंटित कार्यों को देखते हैं। इस प्रकार, वे स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियां नहीं हैं।	बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के दायरे में निम्नलिखित 18 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं: 1. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन; 2. भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन; 3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना; 4. सड़कें और पुल; 5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति; 6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; 7. अग्नि सेवाएं; 8. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन; 9. विकलांग और मानसिक रूप से मंद सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना; 10. स्लम सुधार और उन्नयन; 11. शहरी गरीबी उन्मूलन; 12. शहरी सुविधाओं और पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी सुविधाओं का प्रावधान; 13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना; 14. दफन और कब्रगाह मैदान, श्मशान और शवदाह और विद्युतीकृत श्मशान; 15. मवेशी तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम; 16. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े; 17. सार्वजनिक सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं; तथा 18. बूचड़खानों और टेनरियों का नियमन।

Q.13) चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए हैं?

1. मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2. संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट किया है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

सत्य	असत्य	सत्य
मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उसी तरह और उसी आधार पर उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत्र अपना पद नहीं धारण करता है, हालांकि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।	संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है।	मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है।

Q.14) यूपीएससी (UPSC) से कार्मिक प्रबंधन से संबंधित, निम्नलिखित में से किस मामले पर सलाह ली जाती है?

1. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता।
2. सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित मामले।
3. किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करना।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.14) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
यूपीएससी द्वारा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर; पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी में स्थानान्तरण के लिए; तथा स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियों पर परामर्श दिया जाता है। संबंधित विभाग पदोन्नति के लिए सिफारिशें करते हैं और यूपीएससी से अनुरोध करते हैं कि वे इसकी पुष्टि करें।	यूपीएससी द्वारा सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श लिया जाता है।	किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय UPSC से सलाह नहीं ली जाती है।

Q.15) वित्त आयोग (Finance Commission) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
2. राज्यों को अनुदान सहायता देने से संबंधित वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। तदनुसार, संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्दिष्ट की है	वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं तथा इसलिए, सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। राज्यों को अनुदान देने की इसकी सिफारिशों को लागू करना केंद्र सरकार पर निर्भर होता है।

Q.16) अनुसूचित जाति (SC) के राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. किसी भी शिकायत में पूछताछ करते समय उसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं।
2. आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में समान कार्यों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
आयोग, जब किसी भी मामले की जांच कर रहा होता है या किसी शिकायत की जांच कर रहा होता है, उसके पास दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) की सभी शक्तियाँ होती हैं।	2018 तक, आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के संबंध में समान कार्यों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता थी। यह उत्तरदायित्व से 102 वें संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा समाप्त हुआ

Q.17) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. 101 वें संशोधन अधिनियम ने आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
2. सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना 1993 में की गई थी। बाद में, 2018 के 102 वें संशोधन अधिनियम ने आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338-B जोड़ा है।	आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है

Q.18) जीएसटी परिषद के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्रीय वित्त सचिव, परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
2. परिषद के प्रत्येक निर्णय को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के न्यूनतम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है।
3. केंद्र सरकार के मत का भार, उस बैठक में डाले गए कुल मतों का एक-चौथाई होगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**सत्य**	**असत्य**
केंद्रीय राजस्व सचिव, परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।	परिषद के निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। एक बैठक आयोजित करने के लिए परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का आधा भाग कोरम है। परिषद के प्रत्येक निर्णय को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के न्यूनतम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है।	निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिया जाता है: (i) केंद्र सरकार के मत में उस बैठक में डाले गए कुल मतों का एक तिहाई भारांश होगा। (ii) संयुक्त रूप से राज्य की सभी सरकारों के मतों का भारांश, उस बैठक में डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई होगा।

Q.19) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तों और हटाने के लिए प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।
2. वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के लिए योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तों और हटाने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।	केंद्रीय स्तर पर, आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए, वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

Q.20) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत, आगे किसी कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।
2. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।
3. वह स्थानीय निकायों के खातों का ऑडिट कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत, आगे किसी कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।	उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान उसी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।	वह राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों का ऑडिट।

Q.21) ब्लैक कार्बन (Black Carbon) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्लैक कार्बन प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों दोनों के द्वारा निर्मित होता है।
2. भारत विश्व में ब्लैक कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
3. CO2 की तुलना में, ब्लैक कार्बन कम अवधि के लिए वातावरण में रहता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1, 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2

Q.21) Solution (c)

- जीवाश्म ईंधन और जैवभार (बायोमास) के अधूरे दहन का परिणाम ब्लैक कार्बन के रूप में होता है। जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन, और जैवभार के अधूरे दहन के परिणामस्वरूप ब्लैक कार्बन का उत्पादन प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों दोनों द्वारा किया जाता है।
- प्राथमिक स्रोतों में डीजल इंजन, कुक स्टोव, लकड़ी जलने और जंगल की आग से उत्सर्जन शामिल हैं।
- महीन कण प्रकाश को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग एक मिलियन गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- CO2 के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान ब्लैक कार्बन का है।
- लेकिन CO2 के विपरीत, जो एक साथ वर्षों तक वायुमंडल में रह सकता है, ब्लैक कार्बन अल्पकालिक होता है और वर्षा या बर्फ के साथ नीचे उतरने से पहले केवल कुछ हफ्तों तक वातावरण में रहता है।
- ब्लैक कार्बन सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वायुमंडल को गर्म करता है।
- **भारत विश्व में ब्लैक कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।**
- ब्लैक कार्बन पार्टिकुलेट मैटर का सबसे अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करने वाला घटक है तथा CO2 की तुलना में एक मिलियन गुना अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है।
- ब्लैक कार्बन का न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यह दृश्यता को भी प्रभावित करता है, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, कृषि उत्पादकता को कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है।
- ब्लैक कार्बन और इसके सह-प्रदूषक तत्व सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक हैं, जो खराब स्वास्थ्य और समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख पर्यावरणीय कारण हैं।

Q.22) कोलिस्टिन (Colistin) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कोलिस्टिन एक रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम फल पकाने के लिए किया जाता है।
2. डब्ल्यूएचओ कॉलिस्टिन को मनुष्यों के लिए 'सर्वोच्च प्राथमिकता युक्त गंभीर रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी' मानता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) Solution (b)

- **कोलिस्टिन (Colistin) पशु चिकित्सा में चिकित्सीय उद्देश्य के लिए एक एंटीबायोटिक है।** लेकिन पोल्ट्री उद्योग में रोगनिरोधी उद्देश्य के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए दवा का अत्यधिक

दुरुपयोग किया जाता है। भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का एक कारण पोल्ट्री उद्योग में कोलिस्टिन के अवांछित उपयोग के कारण है।

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने कोलीस्टिन की बिक्री, निर्माण और वितरण पर तथा भोजन वाले जानवरों, मुर्गीपालन, जलीय कृषि और पशु आहार की खुराक में इसके जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से इन जानवरों में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **डब्ल्यूएचओ कॉलिस्टिन को मनुष्यों के लिए 'सर्वोच्च प्राथमिकता युक्त गंभीर रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी' मानता है।**
- AMR (antibiotic resistance) - विशेष रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोध - एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जो माना जाता है कि भारत को भारी रूप से प्रभावित करता है। एंटीबायोटिक्स अप्रभावी होते जा रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं को मारने के लिए प्रतिरोधी हो रहे हैं। इसलिए, जीवाणु संक्रमण अब या तो इलाज करना मुश्किल है या अनुपचारित है। चूंकि समग्र उत्पादित एंटीबायोटिक दवाओं का एक बड़ा हिस्सा भोजन के लिए जानवरों को पालने में उपयोग किया जाता है, ऐसे दुरुपयोग एएमआर के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है।

Q.23) इन्फ्लुएंजा वायरस (Influenza Viruses) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं?

1. इन्फ्लुएंजा A वायरस फ्लू महामारी के कारण ज्ञात एकमात्र इन्फ्लूएंजा वायरस हैं।
2. फ्लू के टीके अन्य वायरस के कारण होने वाले संक्रमण और बीमारी से बचाव करेंगे जो इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण भी पैदा कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (b)

- इन्फ्लूएंजा वायरस के चार प्रकार हैं: A, B, C और D। मानव इन्फ्लूएंजा A और B वायरस संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग हर सर्दी में रोग (फ्लू के मौसम के रूप में जाना जाता है) के मौसमी महामारी का कारण बनते हैं। इन्फ्लुएंजा A वायरस फ्लू की महामारी का कारण बनने वाले एकमात्र इन्फ्लूएंजा वायरस हैं, अर्थात, फ्लू रोग की वैश्विक महामारी। एक महामारी तब हो सकती है जब एक नया और बहुत अलग इन्फ्लूएंजा A वायरस निकलता है जो लोगों को संक्रमित करता है और लोगों में कुशलता से फैलने की क्षमता रखता है।
- इन्फ्लुएंजा टाइप C संक्रमण आम तौर पर हल्की बीमारी का कारण बनता है और मानव फ्लू महामारी का कारण नहीं माना जाता है।
- इन्फ्लुएंजा D वायरस मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है और लोगों में बीमारी को संक्रमित या कारण के लिए नहीं जाना जाता है।

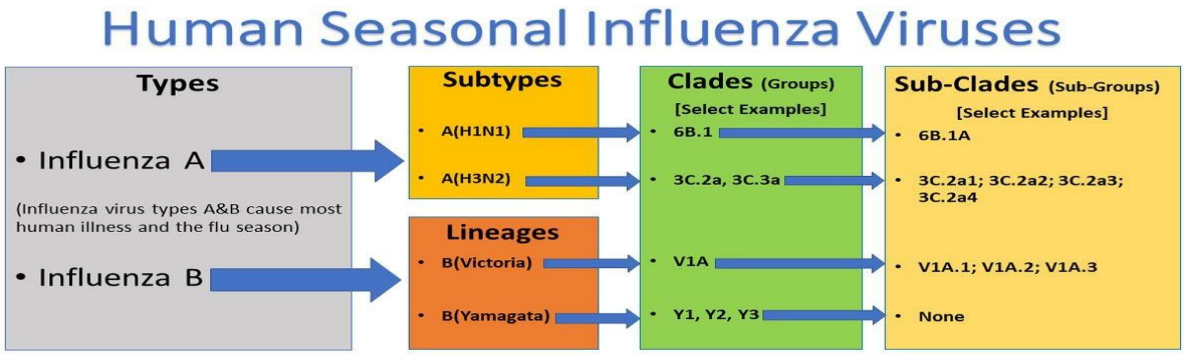

ऊपर दिया गया यह ग्राफ दो प्रकार के इन्फ्लूएंजा वायरस (A, B) को दर्शाता है जो मानव की अधिकांश बीमारियों का कारण बनता है और जो प्रत्येक वर्ष फ्लू के मौसम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्फ्लुएंजा A वायरस को और अधिक उपप्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि इन्फ्लूएंजा B वायरस को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: B/Yamagata और B/Victoria। दोनों इन्फ्लूएंजा A और B वायरस को विशिष्ट रूप से विशिष्ट और उप-समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है (जिन्हें कभी-कभी समूह और उप-समूह कहा जाता है)।

बर्ड फ्लू क्या है?

- एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस बर्ड फ्लू का कारण बनता है। पक्षी, इन्फ्लूएंजा A वायरस और इसके सभी उप-प्रकारों से संक्रमित हो सकते हैं। पक्षी या तो B या C इन्फ्लूएंजा वायरस टाइप को ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं।
- एक इन्फ्लूएंजा महामारी एक नए इन्फ्लूएंजा A वायरस का वैश्विक प्रकोप है।

Q.24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वायुयान पर एविओनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए खतरा पैदा करने वाली सूक्ष्म तरंगों को समाप्त करने के लिए वायुयान में यात्रा करते समय इलेक्ट्रिक उपकरणों को बंद करना महत्वपूर्ण है।
2. भारतीय नियमों के अनुसार, पायलट-इन-कमांड, वाई-फाई ऑन बोर्ड के माध्यम से उड़ान में यात्रियों द्वारा इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की अनुमति दे सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24) Solution (b)

- पायलट-इन-कमांड फ्लाइट में यात्रियों द्वारा इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की अनुमति वाई-फाई ऑन बोर्ड के माध्यम से दे सकता है। पायलट-इन-कमांड द्वारा परमिट के बाद फ्लाइट में यात्रियों को यह सेवा दी जाएगी। यात्री वायुयान में अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ई-रीडर या स्मार्टवॉच के लिए उड़ान सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यह देखते हुए कि उपकरण एयर-प्लेन मोड या फ्लाइट-मोड पर हैं, बशर्ते कि महानिदेशक इंटरनेट सेवा के उपयोग के लिए वाई-फाई ऑन बोर्ड के माध्यम से फ्लाइट में विमान को प्रमाणित करेंगे।
- दिसंबर 2018 में, भारत सरकार ने इन-फ़्लाइट और मैरीटाइम कम्युनिकेशंस (IFMC) के लिए लाइसेंसों की घोषणा की, जो भारतीय आकाश पर उड़ान भरने और भारतीय जल में नौकायन

करते समय, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विमान और जहाजों दोनों के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की अनुमति देता है।

- IFMC लाइसेंस दूरसंचार मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भारत में उपग्रह संचार सेवाओं को उदार बनाने के लिए एक कदम है।
- सरकारी अधिकारी के मुताबिक, उड़ान भरने के बाद ही वाईफाई सेवा का लाभ उठाया जा सकता है तथा जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। विमान में इंटरनेट सेवा का उपयोग महानिदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- विमानों पर एवियोनिक्स तकनीक के लिए खतरा पैदा करने वाली रेडियो तरंगों को समाप्त करने के लिए विमान में यात्रा करते समय इलेक्ट्रिक उपकरणों को बंद करना महत्वपूर्ण है। यह एक कारण है कि यात्रियों को टेक-ऑफ से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने के लिए कहा जाता है।
- यह पता चला है कि उड़ान में वायरलेस उपकरणों पर प्रतिबंध का कारण विमान प्रणालियों के लिए किसी भी खतरे के बजाय जमीनी नेटवर्क के साथ संभावित हस्तक्षेप की बहुत संभावना है। फ़ेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने 1991 में अधिकांश सेल फोन और वायरलेस उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो जमीनी नेटवर्क हस्तक्षेप के कारण का उल्लेख करता है।

Q.25) एंकर निवेशकों (Anchor investors) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें ऑफर खुलने से एक दिन पहले आईपीओ में शेयर दिए जाते हैं।
2. एंकर निवेशक को आवंटन के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए अपना शेयर बेचने की अनुमति नहीं होती है।
3. कोई भी मर्चेंट बैंकर, प्रमोटर या उनके संबंधी एंकर निवेशक श्रेणी के तहत शेयरों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 3
c) केवल 2
d) केवल 2 और 3

Q.25) Solution (c)

- एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें ऑफर खुलने से एक दिन पहले आईपीओ में शेयर दिए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे एक निश्चित मूल्य पर शेयरों की सब्सक्राइब करने के लिए सहमत होकर ऑफर को 'एंकर' करने वाले होते हैं ताकि अन्य निवेशकों को पता चल सके कि ऑफर किए गए शेयरों की मांग है।
- प्रत्येक एंकर निवेशक को इश्यू में न्यूनतम 10 करोड़ रूपए लगाने होते हैं।
- कुल निर्गम आकार का 30 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों को आवंटित किया जा सकता है।
- कोई भी मर्चेंट बैंकर, प्रमोटर या उनके संबंधी एंकर निवेशक श्रेणी के तहत शेयरों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- 250 करोड़ रूपए से कम आकार के प्रस्तावों में, अधिकतम 15 एंकर निवेशक हो सकते हैं, लेकिन 250 करोड़ रूपए से अधिक के प्रस्तावों में, सेबी ने हाल ही में एंकर निवेशकों की संख्या पर सीमा हटा दी है। अब, प्रत्येक अतिरिक्त 250 करोड़ रूपए आवंटन के लिए 10 अतिरिक्त निवेशक हो सकते हैं, प्रति एंकर निवेशक को न्यूनतम 5 करोड़ का आवंटन होना चाहिए।
- यह 2009 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा आरंभ की गई एक अवधारणा है।
- एंकर निवेशक को आवंटन के बाद कम से कम 30 दिनों के लिए अपना शेयर बेचने की अनुमति नहीं होती है।

- एंकर निवेश की मुख्य विशेषताओं में से एक आईपीओ खुलने से एक दिन पहले आवंटन किया जाना है।

Q.26) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. हिमालयी लाल पांडा नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत के मूल स्थानिक है।
2. चीनी लाल पांडा केवल चीन में पाए जाते हैं।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) Solution (a)

चीनी लाल पांडा उत्तरी म्यांमार के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी तिब्बत, सिचुआन और चीन में युन्नान प्रांतों में पाए जाते हैं, जबकि हिमालयी लाल पांडा नेपाल, भारत, भूटान और चीन में दक्षिणी तिब्बत के मूल स्थानिक हैं।

Q.27) 'ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज़ और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey- OBICUS)' किसके द्वारा किया जाता है

a) नीति आयोग
b) भारतीय रिजर्व बैंक
c) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
d) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

Q.27) Solution (b)

रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर विनिर्माण क्षेत्र के ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (OBICUS) का संचालन कर रहा है।

सर्वेक्षण ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग पर मात्रात्मक जानकारी चाहता है, जैसे कि, विनिर्माण गतिविधियों में शामिल कंपनियों से ऑर्डर बुक, बैकलॉग ऑर्डर बुक, कुल इन्वेंटरी, तैयार माल इन्वेंट्री, प्रगति सूची में काम, स्थापित क्षमता, उत्पादन की मात्रा, क्षमता उपयोग, उत्पादन का मूल्य आदि। स्थापित क्षमता, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का मूल्य आदि की जानकारी का उपयोग उद्योग में और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर क्षमता उपयोग की गणना के लिए किया जाता है।

सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण में रिज़र्व बैंक को एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है।

Q.28) एक परिदृश्य पर विचार करें, जिसमें भारत सरकार अपने सकल ऋण कार्यक्रम का एक भाग संप्रभु बांड के माध्यम से उठाना शुरू करेगी। यदि विनिमय दर खराब होने की उम्मीद है, तो

a) घरेलू मुद्रा (INR) में नामित संप्रभु बांड ज़्यादा अच्छा होगा।
b) विदेशी मुद्रा में नामित संप्रभु बांड ज़्यादा अच्छा होगा।
c) बॉन्ड पर विनिमय दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
d) उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, क्योंकि संप्रभु बांड केवल घरेलू मुद्रा में ही दर्शाए जा सकते हैं।

Q.28) Solution (a)

एक बॉन्ड को रुपए में जारी करने और इसे एक विदेशी मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर) में जारी करने के बीच अंतर विनिमय दर जोखिम की घटना है। यदि ऋण डॉलर के संदर्भ में है, और बॉन्ड की अवधि के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो सरकार को डॉलर की समान राशि का भुगतान करने के लिए अधिक रुपये वापस करने होंगे। यदि, हालांकि, प्रारंभिक ऋण को रुपये के रूप में दर्शाया जाता है, तो नकारात्मक गिरावट विदेशी निवेशक पर होगी।

भारत द्वारा दो 10-वर्षीय संप्रभु बांड इश्यू की कल्पना करें: एक अमेरिका में $ 100 के लिए, और दूसरा भारत में 7,000 रुपये के लिए। साधारणतः, मान लीजिए कि विनिमय दर 70 रुपये प्रति डॉलर है। जैसे, इश्यू के समय, दोनों मूल्य समान हैं। अब मान लीजिए कि भारत के लिए विनिमय दर बिगड़ती है और अवधि के अंत में गिरकर 80 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है। पहले मामले में, भारत सरकार को अपने डॉलर-मूल्य वाले दायित्व को पूरा करने के लिए 8,000 रुपये (7,000 रुपये के बजाय जो आरंभ में था) का भुगतान करना होगा। दूसरे मामले में, यह 7,000 रुपये का भुगतान करेगा और ऋणदाता अल्प-परिवर्तित होगा क्योंकि ये 7,000 रुपये अवधि के अंत में सिर्फ $ 87.5 के बराबर होंगे। इसीलिए, यदि विनिमय दर बिगड़ने की आशंका है, तो घरेलू मुद्रा में संप्रभु बांड संप्रभु होना सबसे अच्छा होता है।

Q.29) 'सौर डायनेमिक्स वेधशाला (SDO)' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. SDO का लक्ष्य सौर वातावरण का अध्ययन करके पृथ्वी और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष पर सूर्य के प्रभाव को समझना है।
2. यह इसरो के लिविंग विद अ स्टार (Living with a Star -LWS) कार्यक्रम के तहत पहला उपग्रह है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (a)

सौर गतिशीलता वेधशाला (Solar Dynamics Observatory -SDO) एक नासा मिशन है जो सूर्य का निरीक्षण कर रहा है।

11 फरवरी, 2010 को आरंभ किया गया, वेधशाला लिविंग विथ अ स्टार (LWS) कार्यक्रम का हिस्सा है।

SDO का लक्ष्य अंतरिक्ष और समय के छोटे पैमानों पर और कई तरंग दैर्ध्य में एक साथ सौर वातावरण का अध्ययन करके पृथ्वी और निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर सूर्य के प्रभाव को समझना है।

NOAA 2753 और 2754 के रूप में नामित दो नए सौर धब्बे (sunspots), 24 दिसंबर को NASA के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखे गए।

Q.30) 'हुबली-अंकोला रेलवे लाइन परियोजना' किससे होकर गुजरती है

a) काली टाइगर रिजर्व
b) मैसूर हाथी रिजर्व
c) भद्रा टाइगर रिजर्व
d) बिलिगिरिरंगा स्वामी टाइगर रिजर्व

Q.30) Solution (a)

KARNATAKA

Hubballi-Ankola railway line gets clearance despite opposition